(2) **राजकोषीय उपाय** (Fiscal Measures)—इस श्रेणी में सरकार के वे सभी वित्त सम्बन्धी उपाय आते हैं जो चलन में मुद्रा की मात्रा कम करने में सहायक होते हैं; जैसे—कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। इनसे सम्बन्धित नीतियों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जा रही है :

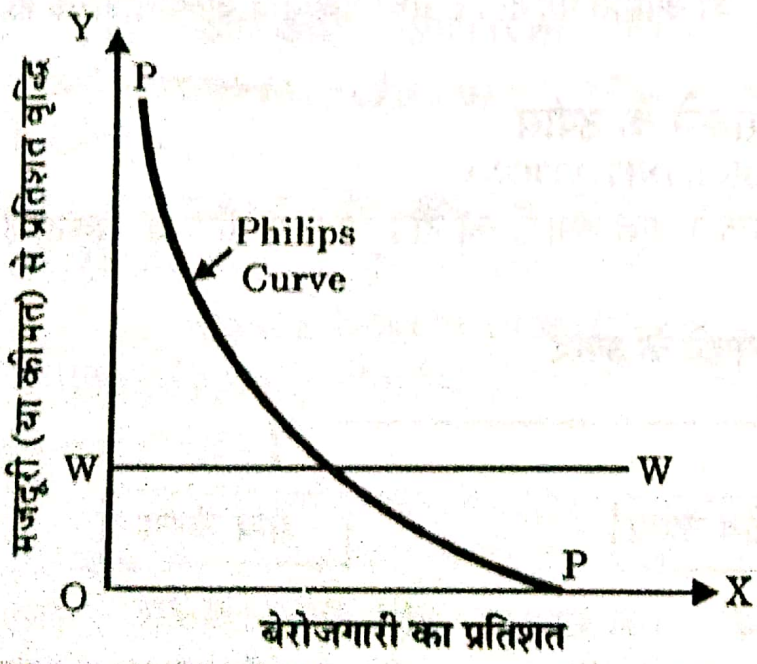

चित्र 5.3

(i) **कर में वृद्धि** (Increase in Taxes)—मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार को जनता की अतिरिक्त क्रय-शक्ति को कम करने हेतु कर में वृद्धि करने की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फालतू क्रय-शक्ति वसूल कर ली जाती है।

(ii) **सार्वजनिक ऋण में वृद्धि** (Increase in Public Debts)—मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिए सरकार को अधिकाधिक मात्रा में लोगों से ऋण वसूल करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त किये गये धन को उत्पादन

Scanned with CamScanner

कार्यों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। परिणामस्वरूप एक ओर तो जनता में क्रय-शक्ति की कमी हो जाती है और दूसरे, उत्पादन की मात्रा भी बढ़ने लगती है।

(iii) **सार्वजनिक व्यय में कमी** (Reduction in Public Expenditure)—स्फीतिकाल में सरकार को चाहिए कि वह यथासम्भव अपने व्यय में कटौती करे, विशेषकर अनुत्पादक व्यय को कम करना अत्यन्त आवश्यक होता है।

(iv) **बचतों को प्रोत्साहन** (Encouragement to Savings)—सरकार की अपनी वित्त सम्बन्धी नीति के द्वारा उपभोग को हतोत्साहित और बचतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाकर तथा बचत सम्बन्धी उपायों का प्रचार कर मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करे।

(v) **विनियोग पर नियन्त्रण** (Control on Investment)—मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे व्यापारी एवं उद्योगपति लाभ कमाकर अपनी पूँजी व्यवसायों के विस्तार में लगाते हैं जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः सरकार को चाहिए कि स्फीति-काल में विनियोग पर नियन्त्रण रखे।

(vi) **मुद्रा का अधिमूल्यन** (Devaluation of Money)—इससे विदेशों को आयात सस्ते और निर्यात महँगे हो जाते हैं। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। आयात बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और निर्यात कम होने से उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि हो जाती है जो बढ़ते मूल्यों पर नियन्त्रण में उपयोगी है।

(3) **अन्य उपाय** (Other Measures)—मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए अन्य उपाय सुझाये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं :

(i) **उत्पादन में वृद्धि** (Increase in Production)—इसके लिए औद्योगिक व कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाये। यह वैज्ञानिक उपकरणों, आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति, मशीनों की व्यवस्था तथा कुशल प्रबन्ध एवं संचालन से सम्भव है। सरकार स्वयं उद्योग खोलकर उत्पादन बढ़ा सकती है।

(ii) **लाभ वितरण पर प्रतिबन्ध** (Restriction on Profit Distribution)—सरकार लाभ वितरण पर प्रतिबन्ध लगाकर हिस्सेदारों के लाभ को उपभोग पर व्यय करने से रोक सकती है। इससे उस सीमा तक मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण सम्भव होगा।

(iii) **सट्टेबाजी पर प्रतिबन्ध** (Restriction on Speculation)—कुछ सट्टेबाज भावी सौदों से ऊँचे मूल्यों का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं जिससे मूल्यों का स्तर अनायास ही बढ़ जाता है। अतः इस पर नियन्त्रण भी सहायक सिद्ध होता है।

(iv) **मूल्य नियन्त्रण व राशनिंग** (Price Control and Rationing)—सरकार अपनी आर्थिक नीति के अन्तर्गत—(अ) वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर विक्रेताओं को बेचने को बाध्य कर सकती है। (ब) सरकार राशनिंग की नीति से आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को रोकने में समर्थ हो सकती है। (स) मजदूरी की अधिकतम दर या Wages Freeze की नीति सहायक सिद्ध होगी। (द) इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की समूची व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले सकती है; जैसे—खाद्यान्नों का शोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

(v) **आयात प्रोत्साहन** (Export Promotion)—वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक आयातों को प्रोत्साहन दे सकती है तथा निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। इससे मुद्रा-प्रसार का प्रभाव रोका जा सकता है।

Scanned with CamScanner